अनूप वधावन, कि विभिन्न कि विभिन्न कि विभिन्न कि विभन्न कि मार्किन कि प्राक्त करण निर्म सचिव, 0100.616 जीनी कि विक्रिक्त कि कि प्रकृतिन उत्तराखण्ड शासन। विकास सम्बद्धा कार्याक

सेवा में.

भाग मार्थिकारी, हिंदी करिए सी विकास करी करिएका में हिस के अपने के कि हिस्सार। के क्यांकर के अपने कार्य के कि कि

शहरी विकास अनुभाग-1 दहरादून : दिनांक 🏌 दिसम्बर, 2009 विषयः आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत कुम्भ मेला—2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रैस कैम्प, मीडिया सेन्टर आदि की स्थापना हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के करते समय कड़ाई से पालेंग कियो जाए।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2565 / कु.मे. / सूचना विभाग दिनांक 30.10.2009 एवं निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2055/सू. एवं लो.स.वि. (प्रशा.) / 2009 दिनांक 20.11.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रैस कैम्प, मीडिया सेन्टर आदि की स्थापना हेतु प्रस्तावित आगणन / प्रस्ताव के सापेक्ष रू. 200लाख (रू. दो करोड़ मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

उक्त कार्य विगत कुम्भ मेला एवं अर्द्धकुम्भ मेले में मदवार व्यय की गई धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अनुमोदित सीमा में ही कराए जाने सुनिश्चित किए जाएंगे लागत में वृद्धि के लिए आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा।

> सूचना विभाग द्वारा अपने कार्य उक्त लागत में ही पूर्ण किए जाने सुनिश्चित किए जाएंगे और इससे अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी। शेष जो भी धनराशि आवश्यक हो. उसे अपने विभागीय बजट से व्यवस्था की जाए।

> स्वीकृत की जा रही धनराशि का वास्तविक आवश्यकतानुसार 04 किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

> उक्तानुसार व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के 80प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने पर ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

5. मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 7. 2008 एवं उक्त के क्रम में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप उपकरण आदि का क्रय विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में 8. मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार किया जाएगा तथा उस पर सक्षम प्राधिकारी से 9. 10 प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाए।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। 10.

एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 12. 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी एवं निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क, 13.

उत्तराखण्ड, देहरादून पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय 14. /भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि 15. कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति

बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 16. दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित

करते समय कडाई से पालन किया जाए।

उपकरणों के क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पूर्व कुम्भ मेलों में क्रय 17. किए गये उपकरणों का भी पूरा उपयोग किया जाए एवं तद्नुसार केवल अतिरिक्त आवश्यक उपकरण ही क्रय किए जाएं। यह भी देख लिया जाए कि यदि उपकरण किराए पर लेना अधिक Cost effective व economical हो तो तद्नुसार ही कार्यवाही की जाए।

जनशक्ति के उपयोग के संबंध में कार्य के मानक निर्धारित कर ही व्यय की सीमा का

आकलन पूर्व में ही कर लिया जाए एवं तद्नुसार ही कार्यवाही की जाए।

उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009-39(सा.)/2006-टी. सी. दिनांक 24नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 100करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 841/XXVII(2)/2009 दिनांक 14दिसम्बर, 2009 में

प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(अनूप वधावन)

संख्या : 1621 (1) / IV(1)/2009 तद्दिनांक । 15/12/09 प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड। 1.

निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून। 3.

महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन। 5.

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी। 6.

जिलाधिकारी, हरिद्वार / देहरादून। 7.

वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार। 8.

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन। 9.

निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।

निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून 11.

गार्ड बुक। 12.

अनुसचिव।